ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-5* August- 2021
Anthology : The Research

भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश शासन के प्रभावों का अध्ययन

Study of the Effects of British Rule in the Indian Economy

Paper Submission: 10/08/2021, Date of Acceptance: 23/08/2021, Date of Publication: 24/08//2021

राकेश चौरे
अतिथि विद्वान,
इतिहास विभाग,
शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य स्वशासी महाविद्यालय, जबलपुर ,
मध्य प्रदेश, भारत

Abstract

ब्रिटिश शासन के प्रभाव में भारत का मौलिक स्वरूप धीरे-धीरे परिवर्तित होना प्रारंभ हुआ, जिसने 1850 के बाद और गति पकड़ी। यह बदलाव यातायात, संचार, व्यवसायिक ढांचा, कृषि व्यवस्था, उद्योग, सामाजिक व्यवहार सभी में देखने को मिला। 17वीं एवं 18वीं शताब्दी के प्रारंभ यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत में तैयार माल यूरोपीय माल के लिए बाजार बहुत सीमित था। वहां अधिकांश आयात भारत से ही होता था। यूरोपीय देश सोने और चांदी की वस्तुएं खरीददारी की कीमत में देते थे।

Under the influence of British rule, the fundamental nature of India gradually began to change, which gained further momentum after 1850. This change was seen in transport, communication, business structure, agricultural system, industry, social behavior all. European trading companies of the 17th and early 18th centuries Finished goods in India The market for European goods was very limited. Most of the imports there were from India. European countries used to give gold and silver items for purchase.

मुख्य शब्दः कृषि, अर्थव्यवस्था, विऔद्योगिकरण

Agriculture, Economy, Industrialization.

प्रस्तावना

भारत में प्रारंभिक आक्रमणकारियों और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों में मुख्य अंतर यह था कि अंग्रेजो के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारंभिक आक्रमणकारी ने ही भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन किया और न ही धन की निरंतर निकासी का सिद्धांत अपनाया। भारत में ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था, उपनिवेशी अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो गयी तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की सभी नीतियां एवं कार्यक्रम उपनिवेशी हितों के अनुरूप बनने लगी।

अध्ययन का उद्देश्य

ब्रिटिश का प्रारंभिक उद्देश्य भारत पर व्यापार करना था न की शासन करना।वह किसी भी प्रकार खतरा नहीं उठाना चाहते थे और न ही सुरक्षा पर अधिक खर्च करना चाहती थी। इसलिये वह मुगल शासन के अधीन रहकर व्यापार करती रही। अंग्रेजों ने अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के उद्देष्य से उसने भूमि पर नियंत्रण स्थापित कर लगान वसूल करना आरंभ कर दिया।

विऔद्योगिकीकरण

भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास 1818 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को भारत से व्यापार करने की छूट मिलने के फलस्वरूप भारतीय बाजार सस्ते एवं मशीन निर्मित आयातित माल से भर गया। दूसरी ओर, भारतीय उत्पादों के लिये यूरोपीय बाजारों में प्रवेश करना अत्यंत कठिन हो गया। 1820 के पश्चात् तो यूरोपीय बाजार भारतीय उत्पादों के लिये लगभग बंद ही हो गये। भारत में रेलवे के विकास ने यूरोपीय उत्पादों को भारत के दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

भारत में परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास इसलिये नहीं हुआ कि यहां औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति हुई, बल्कि यह ह्रास अंग्रेजी माल के भारतीय बाजारों में भर जाने से हुआ क्योंकि भारतीय हस्तशिल्प के सस्ते माल का मुकाबला नहीं कर सका। लेकिन इस अवधि में यूरोप के अन्य

देशों के परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग में भी गिरावट आयी पर इसका कारण वहां कारखानों का विकसित होना था। यह वह समय था जहां एक ओर भारतीय हस्तशिल्प उद्योग तेजी से पतन की ओर अग्रसर था तथा अपनी मृत्यु के कगार पर पहुंच गया था, वहीं दूसरी ओर इस काल में इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रांति तेजी से अपने पैर जमा रही थी तथा देश का तेजी से औद्योगिकीकरण हो रहा था। इस समय भारतीय शिल्पकार एवं दस्तकार पर्याप्त संरक्षण के अभाव में विषम परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे थे, वहीं नये पाश्चात्य अनुप्रयोगों तथा तकनीक ने उनके संकट को और गंभीर बना दिया।[1]

विऔद्योगीकरण का एक और नकारात्मक प्रभाव था- भारत के अनेक शहरों का पतन तथा भारतीय शिल्पियों का गांवों की ओर पलायन। अंग्रेजों की शोषणकारी तथा भेदभावमूलक नीतियों के कारण बहुत से भारतीय दस्तकारों ने अपने परंपरागत व्यवसाय को त्याग दिया तथा वे गांवों में जाकर खेती करने लगे। (उदाहरणस्वरूप बंगाल में कंपनी शासन के दौरान दस्तकारों एवं शिल्पकारों को बहुत कम दरों पर काम करने तथा अपने उत्पाद अत्यंत कम मूल्यों पर बेचने हेतु विवश किया गया।) इससे भूमि पर दबाव बढ़ा अंग्रेज सरकार की कृषि विरोधी नीतियों के कारण यह क्षेत्र पहले से ही संकटग्रस्त था और भूमि पर दबाव बढ़ने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गयी। भारत के उक्त समकालीन आर्थिक विऔद्योगिकीकरण को दादाभाई नौरोजी और रजनी पाम दत्त जैसे विद्वानों ने प्रमुखता से उभरने का कार्य किया और इसी कड़ी में रजनी पाम दत्त ने इंडिया टुडे नामक ऐतिहासिक कृति की रचना की, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तीन चरणों-वाणिज्यिक चरण (1757-1813), औद्योगिक मुक्त व्यापार चरण (1813-1858) और वित्तीय पूंजीवाद (1860 के बाद) का जिक्र करते हुए ब्रिटिश शासन से भारत को हुए आर्थिक नुकसान को दर्शाया है।[2]

कृषि पर प्रभाव

ब्रिटिश शासन स्थापना से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषिजन्य अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अंग्रेजों ने यहां के परंपरागत कृषि ढांचे को नष्ट कर दिया और अपने फायदे के लिए भू-राजस्व निर्धारण और संग्रहण के नए तरीके लागू किये। इस क्रम में उन्होंने किसानों को नकदी फसलों की खेती के लिए बाध्य किया या उन पर करों का बोझ लादा गया और सूर्यास्त कानून जैसे कड़े नियम की व्यवस्था की गयी थी। इस कड़ी में ब्रिटिश शासन द्वारा तीन प्रकार के भूमि बंदोबस्त लागू किये गए, जो निम्नवत है- 1. स्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त 2. रैयतवारी व्यवस्था 3. महालवारी व्यवस्था।[3]

प्लासी युद्ध के पश्चात् बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद बंगाल के गवर्नर-जनरल वॉरेन हेस्टिंग्ज ने 1772 में बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर इजारेदारी प्रथा की शुरूआत भू-राजस्व वसूली के लिए किया। इसके अंतर्गत कंपनी किसी क्षेत्र या जिले के भू-क्षेत्र से राजस्व वसूली की जिम्मेवारी उस व्यक्ति को सौंपता था, जो सबसे अधिक बोली लगाता था। इस ठेका व्यवस्था का कालांतर में बंगाल में बुरा प्रभाव पड़ा, जिससे किसानों का शोषण बढ़ा और भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी। लेकिन कार्नवालिस ने 1793 में इस पंचवर्षीय इजारेदारी व्यवस्था की जगह दस वर्षीय स्थायी/इस्तमरारी/जमींदारी व्यवस्था लागू की। इसके अंतर्गत संपूर्ण ब्रिटिश भारत का 19वीं फीसदी हिस्सा शामिल था। यह व्यवस्था बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश के वाराणसी क्षेत्र तथा उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में लागू की गयी थी। [4] इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार जिन्हें भू-स्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, को अपने क्षेत्रों में भू-राजस्व की वसूली कर उसका दसवां अथवा ग्यारहवां हिस्सा अपने पास रखकर बाकी हिस्सा कंपनी के पास जमा कराना होता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करता था और समय से लगान न देने वालों की जमीनें भी छीन ली जाती थी। इस प्रकार काश्तकार पूरी तरह से जमींदारों की दया पर निर्भर थे। इस व्यवस्था के लाभ के रूप में कंपनी की आय का निश्चित हिस्सा तय हो गया जिस पर फसल नष्ट होने का कोई असर नहीं होता था। दूसरा कंपनी को जमींदार वर्ग के रूप में एक ऐसे वर्ग का सहयोग मिला जो लंबे समय तक कंपनी के प्रति निष्ठावान बना रहा। इस व्यवस्था के अंतर्गत जहां जमींदारों की स्थिति

मजबूत हो गयी, वहीं किसान व्यापक शोषण का शिकार हुए।[5]

ब्रिटिश भारत में दूसरी लगान वसूली व्यवस्था थी-रैयतवारी व्यवस्था। यह भारतीय भू-भाग के कुल 51 प्रतिशत हिस्से पर लगायी गयी थी। इस व्यवस्था का जन्मदाता कैप्टनरीड और थॉमस मुनरो को माना जाता है। यह व्यवस्था तमिलनाडु, मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम व कुर्ग के क्षेत्र में लागू की गयी थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दे दिया गया, जिसके द्वारा ये सीधे या व्यक्तिगत रूप से सरकार की भू-राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, इस व्यवस्था में कृषक ही भू-स्वामी होता था। इस व्यवस्था के दो प्रमुख उद्देश्य थे, 1. भू-राजस्व की नियमित वसूली तथा 2. रैयतों की स्थिति में सुधार लेकिन इनमें दूसरे उद्देश्य की सफलता नकारात्मक रही।

अंग्रेजी भारत में लागू की गयी तीसरी प्रमुख भू-राजस्व व्यवस्था थी, महालवारी व्यवस्था। यह ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रफल के 30 प्रतिशत भाग आरोपित की गयी थी, जिनमें दक्कन के कुछ क्षेत्र संयुक्त प्रांत का आगरा क्षेत्र, अवध, मध्यप्रांत एवं पंजाब के कुछ हिस्से शामिल थे। इस व्यवस्था में भू-राजस्व का निर्धारण महल या समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था और महाल के समस्त कृषक भू-स्वामियों के भू-राजस्व का निर्धारण संयुक्त रूप से किया जाता था। जिसमें गांव के लोग अपने मुखिया या प्रतिनिधियों के द्वारा एक निश्चित समयावधि के अंदर लगान अदायगी की जिम्मेवारी लेते थे। इस व्यवस्था का परिणाम ग्रामीण समुदाय के विखंडन के रूप में सामने आया। सामाजिक दृष्टि से यह व्यवस्था विनाशकारी और आर्थिक दृष्टि से विफल साबित हुई।[6]

निष्कर्ष

निष्कर्षतः यह स्पष्ट है कि अंग्रेजी आर्थिक नीति भारत के आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र के लिए नकारात्मक व शोषणात्मक रही और परिणामस्वरूप भारतीय धन का ब्रिटेन की ओर बर्हिगमन हुआ। भारत का मौलिक स्वरूप धीरे-धीरे परिवर्तित होना प्रारंभ हुआ, जिसने 1850 के बाद और गति पकड़ी। यह बदलाव यातायात, संचार, व्यवसायिक ढांचा, कृषि व्यवस्था, उद्योग, सामाजिक व्यवहार सभी में देखने को मिला।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *महाजन, विद्याधर ; आधुनिक भारत का इतिहास, एस.चंद, पृ. 738-39*
2. *दत्त, रजनी पाम ; आज का भारत*
3. *शुक्ल, आर.एस.; आधुनिक भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय नई दिल्ली विश्वविद्यालय, पृ. 71*
4. *नौरोजी, दादाभाई ; द पावर्टी ऑफ इंडिका पृ. 569*
5. *राव एवं कोण्डावार; मध्यप्रदेष का आर्थिक विकास, 1972 भोपाल*
6. *हजेला, तिलक नारायण ; आर्थिक विचारो का इतिहास।*